



सत्यमेव जयते

आयुक्त (अपील) का कार्यालय,
Office of the Commissioner (Appeal),
केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय, अहमदाबाद
Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.
CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015
07926305065- टेलिफैक्स 07926305136



DIN: 20230864SW000000A72B

स्पीड पोस्ट

- क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STP/3092/2022-APPEAL /14317
- ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-002-APP-66/2023-24
दिनांक Date : 31-07-2023 जारी करने की तारीख Date of Issue 04.08.2023
आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals)
- ग Arising out of Order-in-Original No. CGST/WT07/RAJ/190/2022-23 दिनांक: 13.06.2022 ,
issued by Deputy Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad-North
- घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

1. Appellant

M/s. Mahavirprasad Vishweshwarlaji Prajapati, Block No. 88, New Rajhans
Co-op Housing Society, Nr. Navnirman High School, Ranip, Ahmedabad-
380058

2. Respondent

The Deputy Commissioner, CGST, Division VII, Ahmedabad North
4th Floor, Shajanand Arcade, Nr. Helmet Circle, Memnagar, Ahmedabad-
380052

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

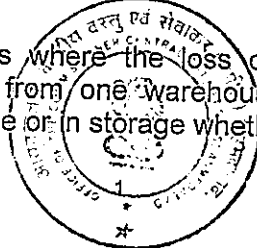
भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.



(क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

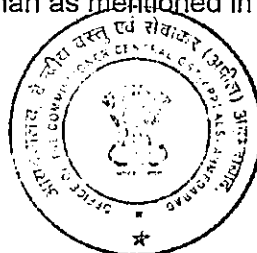
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद -380004

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appel) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (7) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील को मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



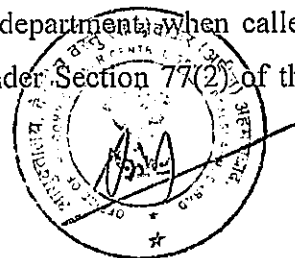
ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Mahavirprasad Vishweshwarlalji Prajapati, Block No. 88, New Rajhans Co. Op. Housing Society, Nr. Navniram High School, Ranip, Ahmedabad – 380058 (hereinafter referred to as “the appellant”) against Order-in-Original No. CGST/WT07/RAJ/190/2022-23 dated 13.06.2022 (hereinafter referred to as “the impugned order”) passed by the Deputy Commissioner, Central GST, Division VII, Ahmedabad North (hereinafter referred to as “the adjudicating authority”).

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are holding PAN No. ANVPP2344J. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the Financial Year 2014-15, it was noticed that the appellant had earned an income of Rs. 10,57,473/- during the FY 2014-15, which was reflected under the heads “Sales / Gross Receipts from Services (Value from ITR)” or “Total amount paid / credited under Section 194C, 194I, 194H and 194J (as shown in Form 26AS)” filed with the Income Tax department. Accordingly, it appeared that the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but had neither obtained Service Tax registration nor paid the applicable service tax thereon. The appellant were called upon to submit copies of Balance Sheet, Profit & Loss accounts, Income Tax Returns, Form 26AS, for the said period. However, the appellant had not responded to the letters issued by the department.

2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice No. CGST/AR-1/Div-VII/A'bad-North/TPD/61/20-21 dated 26.09.2020 demanding Service Tax amounting to Rs. 6,31,609/- for the period FY 2014-15, under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994. The SCN also proposed recovery of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994; and imposition of penalties under Section 77(1)(a), Section 77(1)(c), Section 77(2) and Section 78 of the Finance Act, 1994. The SCN also proposed recovery of un-quantified amount of Service Tax for the period FY 2015-16 to FY 2017-18 (up to Jun-17).

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated, ex-parte, vide the impugned order by the adjudicating authority and the demand of Service Tax amounting to Rs. 6,31,609/- was confirmed under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 along with Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period from FY 2014-15. Further (i) Penalty of Rs. 6,31,609/- was imposed on the appellant under Section 78 of the Finance Act, 1994; (ii) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under Section 77(1)(c) of the Finance Act, 1994 for not submitting documents to the department when called for; and (iii) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under Section 77(2) of the Finance Act, 1994 for contravention of provisions made thereunder.



3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal, along with application of condonation of delay, on the following grounds:

- The appellant is an Individual and engaged into flooring and tiles fitting work. He is not registered with the Services Tax department. The appellant were providing services of fitting the tiles and doing the flooring work in various residential houses. While performing the said work, the appellant have to buy the tiles and various other materials like cement, sand etc. Therefore, it cannot be said that the entire amount received by the appellant is representing the pure nature of service.
- Without prejudice to the above and in the alternative, the appellant have contended that the appellant had provided the services along with material. Hence, receipt ought to have been treated as works contract.
- Due to the non availability of the appellant at his home, the letters as mentioned in the impugned order could not be received by the appellant and therefore the appellant could not submit or file any reply in response to the letters issued by the Revenue.
- The demand for FY: 2014-15 is time barred and therefore, not maintainable. The adjudicating authority has failed to understand that he had issued the show cause notice on 27.09.2020 which is issued in violation of period of limitation.
- The adjudicating authority has failed to appreciate that Service tax liability cannot be determined merely relying upon the data received from CBDT in form of 26AS. The impugned order is passed without looking into the facts, legal provisions, as the demand for financial year 2014-15 is time barred and therefore the same is not maintainable.
- The adjudicating authority has failed to understand that as per the provisions of Section 67(2) of the Finance Act, 1994 provides that for the purpose of valuation of service the amount should be calculated without imposition of any condition. It means that when Service Tax is not collected from service recipient, the same should be considered as inclusive of tax without seeing any further condition. However, the said benefit has not been extended to the appellant by the adjudicating authority.
- The adjudicating authority has failed to appreciate that penalty can be levied only if there is a fraud, collusion, willful misstatement, suppression of facts or contravention of any provisions with intent to evade payment of service tax. The adjudicating authority has not found any of such intent in the order passed by him.



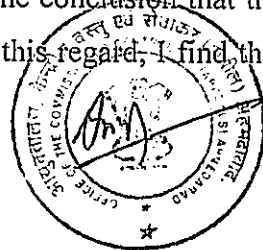
4. Further, on going through the appeal memorandum, it is noticed that the impugned order was issued on 13.06.2022 and received by the appellant on 24.06.2022. However, the present appeal, in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994 was filed on 07.09.2022, i.e. after a delay of 14 days. The appellant have along with appeal memorandum also filed an Application seeking condonation of delay stating that in the preamble of the impugned order, the time period mentioned to file the appeal is 3 months from the date of communication of order. Further, they were unregistered person and had to complete various formalities for payment of pre-deposit. Thus, it resulted in delay of 14 days, which was unintentional and was due to miscommunication / misunderstanding.

5. Personal hearing in the case was scheduled on 17.05.2023, 31.05.2023, 26.06.2023, 14.07.2023, and 24.07.2023. However, neither the appellant nor any representative of the appellant appeared on behalf of the appellant on the date of hearing. Therefore, I take up the case for decision on the basis of the materials available on record.

6. Before taking up the issue on merits, I proceed to decide the Application filed seeking condonation of delay. As per Section 85 of the Finance Act, 1994, an appeal should be filed within a period of 2 months from the date of receipt of the decision or order passed by the adjudicating authority. Under the proviso appended to sub-section (3A) of Section 85 of the Finance Act, 1994, the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay or to allow the filing of an appeal within a further period of one month thereafter if, he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the period of two months. Considering the cause of delay given in application as genuine, I condone the delay of 14 days and take up the appeal for decision on merits.

7. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority, confirming the demand of service tax against the appellant along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period FY 2014-15.

8. I find that in the SCN in question, the demand has been raised for the period FY 2014-15 based on the Income Tax Returns filed by the appellant. Except for the value of "Sales of Services under Sales / Gross Receipts from Services" provided by the Income Tax Department, no other cogent reason or justification is forthcoming from the SCN for raising the demand against the appellant. It is also not specified as to under which category of service the non-levy of service tax is alleged against the appellant. Merely because the appellant had reported receipts from services, the same cannot form the basis for arriving at the conclusion that the respondent was liable to pay service tax, which was not paid by them. In this regard, I find that CBIC had, vide Instruction dated 26.10.2021, directed that:



"It was further reiterated that demand notices may not be issued indiscriminately based on the difference between the ITR-TDS taxable value and the taxable value in Service Tax Returns.

3. It is once again reiterated that instructions of the Board to issue show cause notices based on the difference in ITR-TDS data and service tax returns only after proper verification of facts, may be followed diligently. Pr. Chief Commissioner /Chief Commissioner (s) may devise a suitable mechanism to monitor and prevent issue of indiscriminate show cause notices. Needless to mention that in all such cases where the notices have already been issued, adjudicating authorities are expected to pass a judicious order after proper appreciation of facts and submission of the noticee."

8.1 In the present case, I find that letters were issued to the appellant seeking details and documents, which were allegedly not submitted by them. However, without any further inquiry or investigation, the SCN has been issued only on the basis of details received from the Income Tax department, without even specifying the category of service in respect of which service tax is sought to be levied and collected. This, in my considered view, is not a valid ground for raising of demand of service tax.

9. It is observed that the main contentions of the appellant are that (i) the SCN is issued on 27.09.2020, i.e. after the last date of issuance of the SCN and therefore time barred; (ii) the adjudicating authority has not extended benefit of abatement allowed under work contract service; and (iii) the adjudicating authority has not extended benefit of cum duty as per Section 67(2) of the Finance Act, 1994.

10. I find that the appellant have contended that the demand is barred by limitation. In this regard, I find that the due date for filing the ST-3 Returns for the period April, 2014 to September, 2014 was 14th November, 2014 (as extended vide Order No.02/2014-ST dated 24.10.2014). Therefore, considering the last date on which such return was to be filed, I find that the demand for the period April, 2014 to September, 2014 is time barred as the notice was issued on 26.09.2020, beyond the prescribed period of limitation of five years. I, therefore, agree with the contention of the appellant that, the demand is time barred in terms of the provisions of Section 73 of the Finance Act, 1994. Therefore, the demand on this count is also not sustainable for the period from April, 2014 to September, 2014, as the same is barred by limitation. In this regard, I also find that the adjudicating authority has not taken into consideration the issue of limitation and confirmed the demand in toto.

10.1 For the remaining period from October, 2014 to March, 2015, the due date of filing ST-3 Return was 25th April, 2015. However, due to COVID pandemic, in terms of relaxation provision of Section 6 of Chapter V of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No.2 of 2020) dated 31.03.2020, and the CBIC Notification G.S.R. No. 418(E), dated 27-6-2020, the Central Government had extended the time limit in the taxation and

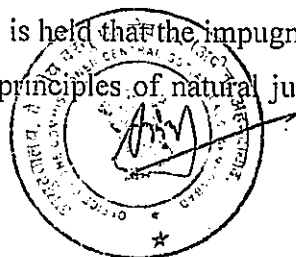
other laws. In terms of said Ordinance, where the time limit specified in an Act falls during the period from 20th March, 2020 to 29th September, 2020, the same shall stand extended to 31st March, 2021. In the instant case, the due date for issuing SCN was 24th April, 2020, but the same was issued on 26th September 2020. Considering the relaxation provided vide above Ordinance in the time limit for issuance of SCN, I find that the notice covering the period from October, 2014 to March, 2015 was issued well within extended period of limitation of five years and is legally sustainable under proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994.

11. As regard, the contention of the appellant that the impugned order was issued without conducting personal hearing, it is observed that the adjudicating authority has scheduled personal hearing by specifying 3 (three) different dates i.e. 19.05.2022, 21.05.2022 and 25.05.2022 in the single letter / notice dated 07.04.2022. The appellant contended that as he was not available at home the letters could not be received by him and he could not attend the personal hearing.

11.1 In this regard, I find that the adjudicating authority has given three dates of personal hearing in one notice and has considered the same as three opportunities. As per Section 33A(2) of the Central Excise Act, 1944, as made applicable to Service Tax vide Section 83 of the Finance Act, 1994, when a personal hearing is fixed, it is open to a party to seek time by showing sufficient cause and in such case, the adjudicating authority may grant time and adjourn the personal hearing by recording the reason in writing. Not more than three such adjournments can be granted. Since such adjournments are limited to three, the hearing would be required to be fixed on each such occasion and on every occasion when time is sought and sufficient cause is made out, the case would be adjourned to another date. However, the adjudicating authority is required to give one date a time and record his reasons for granting adjournment on each occasion. It is not permissible for the adjudicating authority to issue one consolidated notice fixing three dates of hearing, whether or not the party asks for time, as has been done in the present case.

11.2 It is further observed that by notice for personal hearing on three dates and absence of the appellant on those dates appears to have been considered as grant of three adjournments by the adjudicating authority. In this regard, I find that the Section 33A(2) of the Central Excise Act, 1944 provides for grant of not more than 3 adjournments, which would envisage four dates of personal hearing and not three dates. The similar view has been taken by the Hon'ble High Court of Gujarat in the case of Regent Overseas Private Limited and others Vs. Union of India and others reported in 2017 (3) TMI 557 – Gujarat High Court.

11.3 In view of the above, I find that the adjudicating authority was required to give adequate and ample opportunity to the appellant for personal hearing and it is only thereafter, the impugned order was required to be passed. Thus, it is held that the impugned order passed by the adjudicating authority is clearly in breach of the principles of natural justice. The same is not legally sustainable.

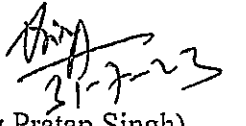


12. The demand needs to be re-quantified considering the fact that the demand for period April, 2014 to September, 2014 is barred by limitation. As regard the contention of the appellant that (i) the service tax required to be calculated after extending benefit of abatement allowed under work contract service; and (ii) they have not charged service tax from the service receivers and therefore provision of Section 67(2) will be applicable and benefit of cum duty valuation is admissible and therefore taxable value is required to be recomputed, the same may also be examined by the adjudicating authority and give appropriate finding on the same while decide the issue.

13. In view of above discussion, I remand the case back to the adjudicating authority to decide the case as per the direction contained here-in-above. Accordingly, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant by way of remand.


14. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

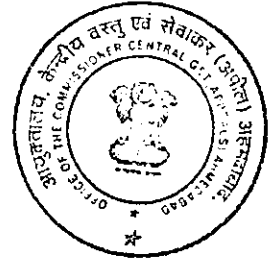
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.


(Shiv Pratap Singh)
Commissioner (Appeals)

Attested

Date : 31.07.2023


(R. C. Maniyar)
Superintendent(Appeals),
CGST, Ahmedabad



By RPAD / SPEED POST

To, .
M/s. Mahavirprasad Vishweshwarlalji Prajapati,
Block No. 88,
New Rajhans Co. Op. Housing Society,
Nr. Navniram High School,
Ranip, Ahmedabad – 380058

Appellant

The Deputy Commissioner,
CGST, Division-VII,
Ahmedabad North

Respondent

Copy to :

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- 2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad North
- 3) The Deputy Commissioner, CGST, Division VII, Ahmedabad North

✓ 4) The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad North
(for uploading the OIA)

5) Guard File

6) PA file

